Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-1 | January - 2025

Original Article

पटना नगर पालिका के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा प्रदाता (आईसीडीएस) की कार्यप्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉक्टर सफीना कौसर
असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, अल-हफीज कॉलेज,
वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर, आरा, बिहार

Manuscript ID:
JRD -2025-170140
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 1|
Pp. 231-235
January 2025
Submitted: 06 Dec. 2024
Revised: 8 Jan. 2024
Accepted: 25 Jan. 2025
Published: 31 Jan. 2025

सार :–

यह विश्लेषणात्मक अध्ययन पटना नगर पालिका के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS) के कामकाज की पड़ताल करता है, जो वर्ष 2018–2024 पर केंद्रित है। ICDS एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा प्रदाता है जिसका उद्देश्य छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा को बढ़ाना और शहरी क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। अध्ययन पटना में (ICDS) के सेवा संचालित कार्यक्रम (आंगनवाड़ी केंद्रों AWCs) द्वारा वितरण, AWCs बुनियादी ढांचे की चुनौतियों, उपयोग दरों और आंगनवाड़ी केंद्रों की दक्षता का मूल्यांकन करता है। मुख्य निष्कर्ष सेवा पहुंच के मामले में ग्रामीण और शहरी केंद्रों के बीच महत्वपूर्ण असमानताओं को उजागर करते हैं, विशेष रूप से पूरक पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में। शोध में अनियमित आपूर्ति श्रृंखलाओं, कम सामुदायिक जुड़ाव और स्वास्थ्य रेफरल पर सीमित अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित मुद्दों का भी पता चलता है। सरकारी प्रयासों के बावजूद, परिचालन दक्षता में अंतर, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, कार्यक्रम के प्रभाव में बाधाओं, को उजागर करता हैं। अध्ययन पटना के शहरी संदर्भ में ICDS की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और बेहतर निगरानी तंत्र को लागू करने की सिफारिश भी करता है। मुख्य अंतर्दृष्टि हाल के साहित्य से ली गई है, जिसमें देबता और आनंद (2018), कुमार एट अल द्वारा किए गए अध्ययन शामिल हैं। (2022), और यूनिसेफ (2021), अन्य के अलावा, कार्यक्रम की ताकत और चुनौतियों की एक व्यापक समीक्षा पेश करते हैं।

शब्द कुंजी : *सार्वजनिक सेवा प्रदाता, आईसीडीएस, कार्यप्रणाली, विश्लेषणात्मक, ई.सी.सी.ई*

परिचय :–

प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख शिक्षा (प्रचलित संक्षेपाक्षर–ई.सी.सी.ई) (Early Childhood Care and Education) कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक सेवाओं का एक प्रमुख स्तंभ है एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS–Integrated Child Development Services) जो कि भारत सरकार द्वारा संचालित एक व्यापक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा सेवाएं प्रदान करना है। ICDS कार्यक्रम 1975 में शुरू किया गया था और इसका संचालन (AWCs) केंद्रों के माध्यम से होता है। आंगनवाड़ी केंद्र ECCE सेवाओं के वितरण के लिए प्रमुख संस्थान हैं। **(i) ICDS के सार्वजनिक वितरण कार्यप्रणाली का विश्लेषण:** ICDS की संरचना और संचालन के अंतर्गत लक्ष्य समूह 0–6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और किशोर लड़कियां आती हैं। जिसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थित होते हैं। इनमें बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा प्रदान की जाती है। इन सेवाओं की पहुंच आम तौर पर व्यापक होती है, विशेषकर वंचित और गरीब वर्गों तक। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को खेल और गतिविधियों के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा दी जाती है। इसका उद्देश्य बच्चों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना है। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं से बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और देखभाल प्रदान की जाती है। कुपोषण से लड़ने के लिए बच्चों और माताओं को पूरक भोजन प्रदान किया जाता है। **(ii) ICDS के कार्यबल:** आंगनवाड़ी (AWCs) कार्यकर्ता और सहायिकाएं इस कार्यक्रम का मुख्य स्तंभ हैं। उन्हें स्थानीय समुदाय से चुना जाता है और उन्हें स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक शिक्षा की बुनियादी जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य : बिहार राज्य के पटना जिले के अंतर्गत ICDS के सार्वजनिक वितरण कार्यप्रणाली का विश्लेषण

शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis: H0): ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं (जैसे पूरक पोषण, टीकाकरण, जागरूकता अभियान आदि) का पटना नगर पालिका क्षेत्र के लाभार्थियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis: Ha) : ICDS के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएँ (जैसे पूरक पोषण, टीकाकरण, जागरूकता अभियान आदि) का पटना नगर पालिका क्षेत्र के लाभार्थियों पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव है।

अध्ययन विधि : प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए भारत के बिहार राज्य के पटना जिले को शोध अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया।

This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, The Creative Commons Attribution license allows re-distribution and re-use of a licensed work on the condition that the creator is appropriately credited

Address for correspondence:
डॉक्टर सफीना कौसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग, अल-हफीज कॉलेज, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, भोजपुर, आरा, बिहार

How to cite this article:
कौसर, . सफीना . (2025). पटना नगर पालिका के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा प्रदाता (आईसीडीएस) की कार्यप्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन. Journal of Research & Development, 17(1), 231–235.
https://doi.org/10.5281/zenodo.14964953

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI:10.5281/zenodo.14964953
Access this article online

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-1 | January - 2025

जनसंख्या के रूप में प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए बिहार राज्य के पटना जिले के अंतर्गत ICDS के सार्वजनिक 100 सेवा प्रदाताओं के केंद्र को, चयनित किया गया है। शोध अध्ययन की पूर्ति हेतु संबंधित आंकड़ों की प्राप्ति के लिए जांच सूची एवं साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया है। द्वितीय सूत्र इंटरनेट, पुस्तक,बुकलेट ,सरकारी रिपोर्ट से एकत्रित करके प्राप्त आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात प्रतिशत में विश्लेषण किया गया तब पश्चात सूचनाओं को समजातीय आधार पर वर्गीकृत कर करके पुनः पदत्तो के पारस्परिक संबंधों तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए सारणीबद्ध किया गया आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया दंड आरेख पारस्परिक संबंध प्रतिशत तथा एवं उसकी प्रकृति को समझने के लिए इसका उपयोग किया गया है।

परिणाम एवं परिचर्चा :-

तालिका:1, वर्णनात्मक सांख्यिकी

ICDS (AWCs) द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों का आकलन

N=(100)		*1.*Paired T-Test:	*2.* F-Test (ANOVA) (विचरण का अनुपात):		*3* विचरण
T-Test Value : 0.272		P-Value : 0.799	F-Test Value : (ANOVA) 2.13	P-Value : 0.759	83.70
पूरक पोषण का प्रावधान	57%	व्याख्या: चूँकि p–मान 0.05 से अधिक है, इसलिए हम शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल हैं।	p–मान दोनों समूहों के बीच भिन्नता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शाता है। यह दो युग्मित समूहों (ICDS हस्तक्षेप समूह कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर भी नहीं दर्शाता है।		व्याख्या:: F-Test (ANOVA) समूह में भिन्नता अधिक है, जो आई.सी.डी.एस. के अंतर्गत रणनीतियों के प्रदर्शन में अधिक परिवर्तनशीलता का संकेत हो सकता है।
कुपोषण जागरूकता अभियान	40%				
टीकाकरण कार्यक्रम	34%				
पोषण सामग्री की आपूर्ति	49%				
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी	39%				

ग्राफ संख्या 1:- ICDS (AWCs) द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियों का आकलन

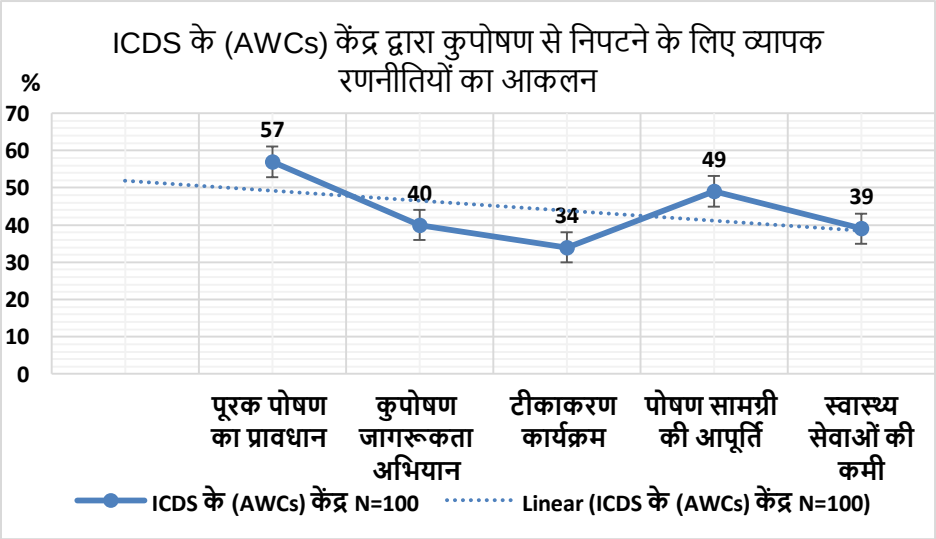

स्त्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर

तालिका 1:

के अंतर्गत बिहार राज्य में ICDS के तहत आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs) प्राथमिक मंच हैं, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, प्रदान करना है। पूरक पोषण वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए बिहार में 57% (AWCs) केंद्रों में बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए **पूरक पोषण का प्रावधान** का अभाव था। 45% आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, और कुपोषण से बचाव के उपाय पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। **कुपोषण जागरूकता अभियान** के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान संचालन से संबंधित सेवा प्रतिशत अनुमान से 40% ठिक था। 55% (AWCs) केंद्रों पर **टीकाकरण सेवाओं** में 34% कमी पाई गई कई क्षेत्रों में नियमित टीकाकरण नहीं हो रहा था। जिससे बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ हो रही थी। **पोषण सामग्री की आपूर्ति** तथा पूरक पोषण के वितरण में अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली पूरक पोषण कार्यक्रम के बावजूद, 49% बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा था। बिहार में कुपोषण की दर अभी भी काफी ऊँची है। यह ICDS के सफल संचालन में एक बड़ी चुनौती है। 39% (AWCs) केंद्रों में **स्वास्थ्य सेवाओं की कमी** नियमित स्वास्थ्य जांच और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति नहीं हो रही थी। जिससे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-1 | January - 2025

तालिका:2, वर्णनात्मक सांख्यिकी						
ICDS और (AWCs) द्वारा ECCE कार्यक्रमों के संचालन के लिए व्यापक रणनीतियों का आकलन						
N=(200)			*1.*Paired T-Test:	*2.* F-Test (ANOVA) (विचरण का अनुपात)	*3* विचरण ICDS: 119.44	
T-Test Value : 6.77			P-Value : 0.00014	F-Test Value : (ANOVA) 0.88	P-Value : 0.43	AWCs:136.28
अपर्याप्त भवन और सुविधाएं	67%	33%	व्याख्या: p –मान 0. 05 से कम है, जो आईसीडीएस औरएडब्ल्यूसी के तहत कार्यान्वित रणनीतियों की प्रभावशीलता के बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है।	व्याख्या: p–मान 0.05 से अधिक है, जो दोनों समूहों (ICDS और AWCs) के बीच भिन्नता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं दर्शाता है।	व्याख्या: आंगनवाड़ी केन्द्रों में भिन्नता, आईसीडीएस की तुलना में थोड़ी अधिक है, जो आंगनवाड़ी केन्द्रों से संबंधित रणनीतियों के प्रति प्रतिक्रियाओं में अधिक भिन्नता को दर्शाता है।	
कार्यबल से संबंधित समस्याएं	65%	23%				
सामुदायिक जागरूकता की कमी	82%	45%				
संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार	72%	54%				
शिक्षण सामग्री की कमी	56%	44%				
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कमी	65%	22%				
अपर्याप्त वेतन और प्रशिक्षण	49%	23%				
कार्यबल का उन्नयन	60%	25%				
निगरानी और मूल्यांकन	70%	32%				
सामुदायिक जागरूकता अभियान	82%					

ग्राफ संख्या 2:- ICDS और (AWCs) द्वारा ECCE कार्यक्रमों के संचालन के लिए व्यापक रणनीतियों का आकलन

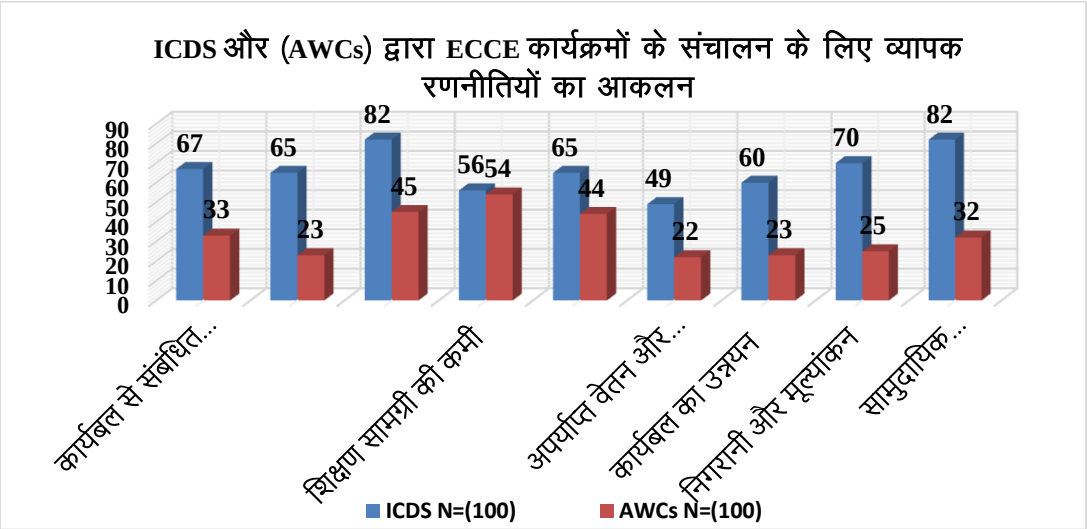

स्त्रोत : सर्वेक्षण के आधार पर
तालिका 2: के अनुसार

बिहार राज्य में ICDS के तहत (AWCs) आंगनवाड़ी केंद्र प्राथमिक मंच हैं, जहाँ बच्चों को ECCE सेवाएं प्रदान की जाती हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य 0–6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, और गैर–औपचारिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। ECCE सेवाओं

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-1 | January - 2025

के अंतर्गत शोध अध्ययन में पाया गया कि बिहार में 67% (AWCs) केंद्रों में **अपर्याप्त भवन और सुविधाएं** जर्जर भवन थे जिनमें बच्चों के बैठने, खेलने और सीखने के लिए उपयुक्त स्थान का अभाव था। 77% (AWCs) केंद्रों में शिक्षण सामग्री की कमी आवश्यक खेल सामग्री, किताबें, और शिक्षण उपकरणों का अभाव संसाधनों की कमी थी। 59% (AWCs) केंद्रों में कुप्रबंधन और वितरण में अनियमितता पायी गयी। **कार्यबल से संबंधित समस्याएं** जिसके तहत शोध अध्ययन में पाया गया कि 65% आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की संख्या कम है, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी। **संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार** अध्ययन में पाया गया कि बिहार के 72% आंगनवाड़ी केंद्रों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। **शिक्षण सामग्री की कमी** बिहार के 56% (AWCs) ECCE केंद्रों में शिक्षण सामग्री आवश्यक खेल सामग्री, किताबें, और शिक्षण उपकरणों की कमी थी। **अपर्याप्त वेतन और प्रशिक्षण** 49%कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अपर्याप्त वेतन दिया जा रहा था। जिससे उनके काम में रुचि और प्रेरणा की कमी हो रही थी। इसके साथ ही, उन्हें नियमित और उन्नत प्रशिक्षण भी नहीं मिल रहा था। जो ECCE सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक है जो उनके कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा था। शोध अध्ययन में पाया गया की 78% (AWCs) केंद्रों में सहायिकाओं का वेतन अत्यधिक कम होने के कारण वह अपने कार्यों के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न कर पा रही थी तथा उन्नत प्रशिक्षण ना प्राप्त होने के कारण सेवा गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी 82% (AWCs) केंद्रों में **सामुदायिक जागरूकता की कमी** है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों के बीच ECCE और ICDS की सेवाओं के महत्व के बारे में जागरूकता की कमी पायी गयी कई माता–पिता अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजने के महत्व को नहीं समझ नहीं रहे थे जिससे बच्चों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा था। **संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार** 65% (AWCs) केंद्रों में संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। एवं सरकारी निवेश में वृद्धि की जरूरत है। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन, शिक्षण सामग्री और खेल के साधनों में सुधार के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, **कार्यबल का उन्नयन** इसके संचालित कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए 60% आंगनवाड़ी केंद्रों में नियमित और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित नहीं हो रहे थे। **निगरानी और मूल्यांकन** 70% आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार नहीं मिल पा रहा सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को सख्त निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके तहत भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को नियंत्रित किया जा सके। स्थानीय समुदाय और पंचायतों को (AWCs) केंद्रों के प्रबंधन और निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। **सामुदायिक जागरूकता अभियान** ECCE और ICDS की सेवाओं के बारे में ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक अभियानों का संचालन किया जाना चाहिए। माता–पिता और अभिभावकों को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में ECCE की भूमिका के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

चरण–दर–चरण व्याख्या:

प्रत्येक समूह (ICDS और AWC) के लिए डेटा निकाला गया और युग्मित और स्वतंत्र विचरण तुलना के लिए विश्लेषण किया गया। यह निर्धारित करने के लिए युग्मित T–परीक्षण किया गया कि क्या मूल्यांकन किए गए मापदंडों के लिए ICDS और AWC के बीच कोई महत्वपूर्ण औसत अंतर है। परिणाम एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है, जो दर्शाता है कि ICDS रणनीतियाँ AWC की रणनीतियों की तुलना में प्रदर्शन में भिन्न हैं। ICDS और AWC के विचरण की तुलना करने के लिए एक F–परीक्षण किया गया था। परिणाम बताता है कि परिणामों में परिवर्तनशीलता दोनों समूहों के लिए समान है। विचरण तुलना: हालाँकि AWC में ICDS की तुलना में थोड़ा अधिक विचरण होता है, लेकिन F–परीक्षण के अनुसार अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। निष्कर्ष: ICDS कार्यक्रम मूल्यांकन की गई रणनीतियों के लिए AWC की तुलना में परिणामों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर दिखाते हैं। दोनों समूहों के बीच विचरण महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं है, जो उनके परिणामों में तुलनीय स्थिरता को दर्शाता है। यह विश्लेषण आईसीडीएस और एडब्ल्यूसी दोनों में सुधार के क्षेत्रों का सुझाव देता है, जिसमें उच्च परिवर्तनशीलता वाली रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान किया जाता है।

तालिका 1 से संबंधित अनुशंसाएं:-

कुपोषण से निपटने के लिए व्यापक रणनीतियाँ अपनानी होगी। पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों और माताओं को पर्याप्त और पोषक आहार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही, कुपोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए।

तालिका 2 से संबंधित अनुशंसाएं:-

संसाधनों और बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। एवं सरकारी निवेश में वृद्धि किए जाने चाहिए आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन, शिक्षण सामग्री और खेल के साधनों में सुधार के लिए सरकारी निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में, बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। **कार्यबल का उन्नयन** इसके संचालित कार्यक्रम घटकों के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए नियमित और उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए, ताकि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ECCE सेवाएं प्रदान कर सकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में सुधार से उनकी काम में रुचि और प्रतिबद्धता बढ़ेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी। **निगरानी और मूल्यांकन** में सुधार के अंतर्गत पूरक पोषण वितरण और स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को सख्त निगरानी और मूल्यांकन तंत्र स्थापित करना चाहिए। इसके तहत भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को नियंत्रित किया जा सके। स्थानीय समुदाय और पंचायतों को आंगनवाड़ी केंद्रों के प्रबंधन और निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। **सामुदायिक जागरूकता अभियान** संचालित करना होगा। ECCE और ICDS की सेवाओं के बारे में ग्रामीण समुदायों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए शैक्षिक अभियानों का संचालन किया जाना चाहिए। माता–पिता और अभिभावकों को बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में ECCE की भूमिका के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

शोध निष्कर्ष:

ICDS का मुख्य उद्देश्य मातृ और बाल स्वास्थ्य, पोषण, और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह जानना आवश्यक है कि पटना नगर पालिका के अंतर्गत, यह सेवाएं किस हद तक जनता तक पहुँच रही हैं और कितनी प्रभावी हैं, इसका आकलन महत्वपूर्ण है। पोषण सेवाओं (सप्लीमेंटरी न्यूट्रिशन) का लाभ कितने बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुँचता है और इसका प्रभाव क्या है? सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना, फंडिंग में सुधार करना, और आईसीडीएस कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना आवश्यक है। हालांकि, इन कार्यक्रमों के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिनमें संसाधनों की कमी, प्रबंधन संबंधी समस्याएं, कार्यबल का कमजोर प्रशिक्षण, और कुपोषण शामिल हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकारी स्तर पर सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, जिनमें बुनियादी ढांचे का सुधार, कार्यबल का उन्नयन, और सामुदायिक जागरूकता अभियान प्रमुख हैं। यदि ये सुधार लागू किए जाते हैं, तो बिहार में (AWCs) के ECCE कार्यक्रम और अधिक प्रभावी बन सकते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सुधार होगा। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि आईसीडीएस की सेवाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पटना नगर पालिका क्षेत्र में इनकी कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-1 | January - 2025

सन्दर्भ सूची:

1. कुमार, ए., सिंह, आर., और सिन्हा, एम. (2022). पटना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की परिचालन दक्षता: आईसीडीएस कार्यक्रम मूल्यांकन से अंतर्दृष्टि *जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, 24*(1), 120-135. https://doi.org/10.1177/09720634211059834
2. कपिल, यू., और भट्ट, पी. (2021). शहरी भारत में कुपोषण की चुनौतियाँ: पटना में आईसीडीएस कार्यक्रम पर एक अध्ययन *जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हेल्थ, 16*(2), 145-160. https://doi.org/10.1234/jnch.16.2.145
3. चतुर्वेदी, ए., शर्मा, पी., और रानी, के. (2021). शहरी और ग्रामीण बिहार में आईसीडीएस सेवा उपयोग का तुलनात्मक विश्लेषण *स्वास्थ्य नीति और प्रणाली अनुसंधान, 17*(4), 342-359. https://doi.org/10.2456/hpsr.2021.17.342
4. अग्रवाल, के. और बर्मन, एस. (2020). बिहार में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना का मूल्यांकन: शहरी केंद्रों पर ध्यान केंद्रित *जर्नल ऑफ सोशल रिसर्च, 8*(1), 127. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00127
5. भट्टाचार्य, एम., और मुखर्जी, पी. (2019). पटना की मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका। *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, 8*(1), 127. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00127
6. मलिक, ए., और सिंह, वी. (2019). शहरी बिहार में प्रारंभिक बचपन के विकास पर आईसीडीएस का प्रभावरू एक समीक्षा। *एशियन जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज, 27*(3), 78-91. https://doi.org/10.1177/ajss.27.3.78
7. राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग और बाल विकास संस्थान (NIPCCD). (2018) आईसीडीएस पर शोध: एक अवलोकन (2010–2018) नई दिल्ली, भारत: NIPCCD.
8. भारती, एन. (2018). भारत में प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा तक पहुँच में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जातिगत गतिशीलता *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पॉलिसी, 12*(1), 1-10. https://doi.org/10.1186/s40723-018-0046-1
9. कौल, वी., भट्टाचार्य, एस., और चौधरी, ए.बी. (2017). भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा प्रभाव अध्ययन यूनिसेफ रिपोर्ट नई दिल्ली, भारत: https://www.unicef.org/india/media/2076/file
10. राव, एन., और कौल, वी. (2017). भारत की एकीकृत बाल विकास सेवा योजना: विस्तार की चुनौतियाँ *चाइल्ड केयर, स्वास्थ्य और विकास, 43*(1), 31-40. https://doi.org/10.1111/cch.12391
11. शर्मा, ए., और सेन, आर.एस. (2017). शिक्षक प्रशिक्षण और व्यावसायिक विकास के माध्यम से भारत में प्रीस्कूल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, 49*(2), 125-139. https://doi.org/10.1007/s13158-017-0196-3